

[2011] 5 एस. सी. आर. 518

मु. मन्नान उर्फ अब्दुल मन्नान

बनाम

बिहार राज्य

(2009 की आपराधिक अपील सं. 379)

अप्रैल 20,2011

[हरजीत सिंह बेदी और चंद्रमौली कुमार प्रसाद, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860: उपधारा 304 बी और 201 संयुक्त पठन धारा धाराएँ 366, 376, 302, 201 - सात साल की लड़की का बलात्कार और हत्या-परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि-यह आरोप कि आरोपी पीड़िता के दादा के घर में राजमिस्त्री के रूप में काम कर रहा था-आरोपी ने पीड़िता को उसके लिए पान लाने के लिए पान की दुकान पर भेजा-पीड़िता के जाने के कुछ मिनट बाद, आरोपी पान की दुकान की ओर बढ़ा और पीड़िता को अपनी साइकिल पर बैठा लिया-पीड़िता को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था-आरोपी द्वारा स्वीकारोक्ति कि उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी-आरोपी द्वारा दिए गए बयान के अनुसार पाया गया पीड़िता का शव-निचली अदालतों ने आरोपी को दोषी ठहराया और मौत की सजा का आदेश दिया-आयोजित:परिस्थितियों ने निर्दोष रूप से आरोपी के अपराध की ओर इशारा किया और कड़ी इतनी पूरी थी कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सका कि अपराध आरोपी द्वारा किया गया था और कोई और नहीं-दोषसिद्धि बरकरार-सजा के संबंध में, आरोपी लगभग 43 वर्ष का एक परिपक्व व्यक्ति था और विश्वास का पद रखता था और एक सुनियोजित और पूर्व नियोजित तरीके से उसका दुरुपयोग किसर था-पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बच्चे के चेहरे, नाखूनों और शरीर पर विभिन्न चोटें

दिखाई दीं-ये चोटें उस वीभत्स तरीके को दर्शाती थीं जिसमें उसे बलात्कार का शिकार बनाया गया था-पीड़ित एक निर्दोष बच्ची थी जिसने कोई बहाना भी नहीं दिया, हत्या के लिए उकसाना भी बहुत कम था-इस कृत्य ने निस्संदेह समुदाय को अत्यधिक क्रोधित किया और समाज की सामूहिक अंतरात्मा को चौंका दिया था-मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है और निचली अदालतों ने सही ढंग से मृत्युदंड/सजा सुनाई है।

साक्ष्य: परिस्थितिजन्य साक्ष्य-आयोजित:परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए-इस तरह से साबित की गई परिस्थितियों को अभियुक्त के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए-यह पूरी श्रृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और किसी ने नहीं-इस तरह की सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर विचार किया जाना चाहिए और काल्पनिक तरीके से नहीं-साक्ष्य केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप नहीं होने चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होने चाहिए।

सजा/सजा:मृत्युदंड देने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश-चर्चा की गई।

अभियोजन पक्ष का मामला था कि पीड़िता 7 साल की लड़की थी। अपीलार्थी अभि.ग.-8 के घर में राजमिस्त्री के रूप में काम कर रहा था जो पीड़िता के दादा थे। दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अपीलार्थी ने पीड़ित को पान लेने के लिए पान की दुकान पर भेजा और कुछ मिनटों के बाद वह पान की दुकान की ओर बढ़ा और पीड़ित को अपनी साइकिल के कैरियर पर बैठाया। अभि.ग.5 और अन्य महिलाओं ने पीड़िता को अपीलकर्ता के साथ साइकिल पर जाते हुए देखा। पीड़िता घर नहीं लौटी। पीड़िता के चाचा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पीड़िता की तलाश में गए और अपीलार्थी को देखा। अपीलार्थी ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़ लिया गया। अपीलार्थी ने इकबालिया बयान दिया कि उसने

पीड़िता के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। उनके द्वारा दिए गए बयान से पीड़िता का शव बरामद हुआ।

निचली अदालत ने माना कि सभी परिस्थितियां अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करती हैं और उसे भा.दं.सं. की धारा 366,376,302,201 के तहत दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और मृत्युदंड की पुष्टि की। दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल अपील दायर की गई थी।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित: 1.1.परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार साबित की गई परिस्थितियाँ निर्विवाद रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हैं। इसे एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि अपराध आरोपी द्वारा किया गया था और कोई और नहीं। इस पर सभी मानवीय संभावनाओं के तहत विचार किया जाना चाहिए न कि काल्पनिक तरीके से। इस तरह के साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए बल्कि उसकी बेगुनाही के साथ भी असंगत होने चाहिए। यह कहने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं लगाया जा सकता है कि विशेष परिस्थितियाँ अपराध को स्थापित करने के लिए निर्णायक हैं। यह मूल रूप से साक्ष्य की सराहना का सवाल है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कौन सा अभ्यास किया जाना है। [पैरा 11] [528-ए-डी]

1.2. गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी मृतक के दादा, अभि.ग. 8 के घर में राजमिस्त्री के रूप में काम कर रहा था और मृतक को उसने पान लेने के लिए पान की दुकान पर भेजा था। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य ने सभी उचित संदेह से परे साबित किया कि अपीलार्थी मृतक के जाने के कुछ मिनट बाद पान की दुकान की ओर बढ़ा

और यह अपीलार्थी ही था जिसे आखिरी बार मृतक के साथ साइकिल पर एक साथ जाते देखा गया था। ऐसे भारी प्रमाण थे जो किसी भी संदेह की छाया से परे साबित करते थे कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए बयान से मृतक का शव खेत से बरामद हुआ। इस प्रकार परिस्थितियाँ अपीलार्थी के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं और श्रृंखला इतनी पूर्ण थी कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि अपराध अपीलार्थी द्वारा किया गया था और कोई और नहीं। तदनुसार, अपीलार्थी की दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है। [पैरा 15] [530-बी-डी]

2.1. यह सामान्य बात है कि मौत की सजा केवल ऐसे मामले में दी जा सकती है जो दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है, लेकिन इस परेशान करने वाले मुद्दे को तय करने के लिए कोई कठोर और त्वरित नियम और मापदंड नहीं है। फिर भी यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि इस प्रश्न का निर्णय लेने में मारे गए व्यक्तियों की संख्या निर्णायक नहीं है। आगे, अपराध क्रूर और जघन्य है स्वयं पैमाने को मौत की सजा की ओर न मोड़ें। जब अपराध अत्यंत क्रूर, घृणित, शैतानी, विद्रोही या डरपोक तरीके से किया जाता है जिससे कि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक रोष उत्पन्न हो और जब समुदाय की सामूहिक चेतना भयभीत हो जाती है तो व्यक्ति को मृत्युदंड की ओर झुकना पड़ता है। लेकिन यह अंत नहीं है। यदि ये कारक मौजूद हैं तो अदालत को यह देखना होगा कि क्या आरोपी समाज के लिए खतरा है और इसके शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है। अदालत को आगे पूछताछ करनी होगी और यह विश्वास करना होगा कि दोषी ठहराए गए आरोपी को सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है और आपराधिक कृत्यों को जारी रखा जाएगा। इस प्रकार गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों में मृत्युदंड के अधिरोपण पर विचार करते समय एक तुलनपत्र तैयार किया जाना चाहिए और न्यायसंगत संतुलन बनाया जाना चाहिए। जब तक कानून में मौत की सजा का प्रावधान है और जब समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा भयभीत होती है, तो यह उम्मीद की जाती है कि न्यायिक

शक्ति के धारक अस्फुट वाणी बोलते हैं, अपनी व्यक्तिगत राय नहीं देते हैं और मौत की सजा नहीं देते हैं। [पैरा 17] [530-एफ-एच; 531-ए-ई]

2.2. हाथ में मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। अपीलार्थी लगभग 43 वर्ष की आयु का एक परिपक्व व्यक्ति था। उन्होंने विश्वास का पद संभाला और सुनियोजित और पूर्व नियोजित तरीके से इसका दुरुपयोग किया। उसने लगभग 7 साल की लड़की को पान खरीदने के लिए भेजा और उसके कुछ मिनट बाद अपनी शैतानी और विचित्र इच्छा को पूरा करने के लिए उस दुकान की ओर बढ़ा जहाँ उसे भेजा गया था। लड़की की उम्र लगभग 7 साल पतली और 4 फीट ऊँची थी और ऐसी बच्ची सामान्य स्थिति में वासना पैदा करने में असमर्थ थी। अपीलार्थी ने बच्चे का विश्वास जीता था और वह अपीलार्थी की इच्छा को नहीं समझ पाई थी जो इस तथ्य से स्पष्ट होगा कि जब उसे अपीलार्थी द्वारा ले जाया जा रहा था तो कोई विरोध नहीं किया गया था और निर्दोष बच्चे को अपीलार्थी की वासना का शिकार बनाया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बच्चे के चेहरे, नाखूनों और शरीर पर विभिन्न चोटें दिखाई दीं। ये चोटें उस वीभत्स तरीके को दर्शाती हैं जिसमें उसके साथ बलात्कार किया गया था। अपराध का शिकार एक निर्दोष बच्ची थी जिसने एक बहाना भी नहीं दिया, हत्या के लिए उकसाने से बहुत कम। एक छोटे बच्चे के प्रति ऐसी क्रूरता भयावह है। अपीलार्थी इतना नीचे गिर गया था कि निर्दोष, असहाय और रक्षाहीन बच्चे पर अपना राक्षसी स्वभाव छोड़ दिया। इस कृत्य ने निस्संदेह समुदाय के अत्यधिक आक्रोश को आमंत्रित किया था और समाज की सामूहिक अंतरात्मा को सदमा दिया था। निर्णय लेने की शक्ति से प्रदत्त अधिकारी से उनकी अपेक्षा मृत्युदंड देने की है जो स्वाभाविक और तार्किक है। अपीलार्थी समाज के लिए एक खतरा है और ऐसा ही बना रहेगा और उसे सुधारा नहीं जा सकता है। यह मामला दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है और निचली अदालत ने मौत की सजा सही ढंग से सुनाई थी जिसकी उच्च न्यायालय ने सही पुष्टि की थी। [पैरा 18] [531 • ई-एच; 532-ए-डी]

आपराधिक याचिका क्षेत्राधिकार: 2009 की आपराधिक अपील सं. 379।

2007 के सी. आर. ए. डी. बी. सं. 963 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 19.08.2008 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए आफताब अली खान, एम. जेड. चौधरी

प्रत्यर्थियों के लिए गोपाल सिंह

न्यायालय का निर्णय चंद्रमौली कु. प्रसाद, न्या. ने दिया।

1. अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 366, 376, 302 और 201 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'दंड संहिता' कहा गया है) के अधीन अपराध के लिए विचारण किया गया था। निचली अदालत ने 29 मई, 2007, दिनांकित अपने फैसले और आदेश द्वारा मणिगाची थाना केस नं. 13, 2004, से उत्पन्न 2004 के सेशन ट्रायल नं. 220, में पारित अपीलार्थी को सभी आरोपों का दोषी ठहराया एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध के लिए 10 साल का कठोर कारावास, दंड संहिता की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास, दंड संहिता की धारा 201 के तहत अपराध के लिए 7 साल का कठोर कारावास और दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई। निचली अदालत ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को संदर्भित किया जिसके कारण 2007 की मृत्यु संदर्भ संख्या 6 का पंजीकरण हुआ। अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि और दंड से व्यथित होकर अपील भी की जो 2007 की आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 963 के रूप में पंजीकृत थी। संदर्भ और अपील दोनों की सुनवाई एक साथ की गई और 19 अगस्त, 2008 को एक समान निर्णय द्वारा, पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निर्देश को स्वीकार कर लिया और अपील को खारिज कर दिया।

2. इस प्रकार अपीलार्थी न्यायालय की अनुमति से हमारे समक्ष है।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता मोहम्मद मन्नान राजमिस्त्री के रूप में काम कर रहा था और मुखबिर के चाचा अभि. सं.- 8 देवकांत झा के घर पर प्लास्टर के काम में लगा हुआ था। 28 सितंबर, 2004 को, अपीलार्थी ने हनुमान चौक की एक दुकान से पान लाने के लिए लगभग 8 वर्ष की आयु के मुखबिर की भतीजी, अर्थात् कल्याणी कुमारी को 2/- रुपए दिए। कुछ समय बाद, अपीलार्थी ने काम छोड़ दिया, हनुमान चौक पर गया और अपनी साइकिल पर कल्याणी कुमारी को बैठाया। पी डब्ल्यू-५ माया देवी और अन्य महिलाओं ने वह बातचीत सुनी जो अपीलार्थी कल्याणी कुमारी के साथ कर रहा था। महिलाओं के अनुसार, अपीलकर्ता ने कल्याणी कुमारी से पूछा कि उनके पिता कहां रहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह बॉम्बे में रहते हैं। कुछ देर तक जब कल्याणी कुमारी घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई और उसके बाद पता चला कि वह एक आदमी के साथ साइकिल पर जा रही है। मुखबिर शरवण कुमार झा (पीडब्ल्यू-१०) और उसके परिवार के सदस्य लड़की की तलाश में निकले और जब वे बहेरा से लौट रहे थे, तो उन्होंने अपीलकर्ता को बहेरा की ओर जाते हुए देखा। अपीलार्थी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और पूछताछ में उसने लड़की के बारे में अनभिज्ञता दिखाई। अपीलार्थी को मुखबिर के निवास पर लाया गया जहां पीडब्ल्यू-5 माया देवी ने खुलासा किया कि उन्होंने अपीलार्थी को अपनी साइकिल पर कल्याणी कुमारी को दूर ले जाते देखा था। इसके बाद, अपीलार्थी को पुलिस स्टेशन लाया गया और उचित कार्रवाई करने के लिए, एक लिखित रिपोर्ट के साथ प्रभारी अधिकारी को सौंप दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी ने कल्याणी कुमारी का अपहरण कर लिया था। उपरोक्त जानकारी के आधार पर, एक मामला दर्ज किया गया और पीडब्ल्यू-11 हरिराम, प्रभारी अधिकारी ने जांच शुरू की।

4. जांच के दौरान, अपीलार्थी ने गवाह अमर किशोर झा (पीडब्ल्यू-2) और देवी कांत झा (पीडब्ल्यू-8) और अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में एक इकबालिया बयान दिया। अपीलार्थी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उस स्थान का खुलासा किया जहां उसने कल्याणी

कुमारी का बलात्कार और हत्या की थी। अपीलार्थी द्वारा दिए गए बयान से कल्याणी कुमारी के शव को एक खेत से बरामद किया गया। सूचना देने वाले और अन्य ग्रामीणों ने उसकी पहचान की। कल्याणी कुमारी के मृत शरीर के निजी अंगों पर चोट के निशान थे, उसके नाखून मुंडवा दिए गए थे और पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। जांच रिपोर्ट तैयार की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसका संचालन पीडब्ल्यू-4 डॉ. प्रफुल्ल कुमार दास, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग में एक शिक्षक द्वारा किया गया। पुलिस ने सामान्य जांच के बाद अपीलकर्ता के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और एक नाबालिग लड़की की हत्या और अपराध के सबूतों को गायब करने के लिए आरोप पत्र दाखिल किया। अपीलार्थी को अंततः मुकदमे का सामना करने के लिए सेशन न्यायालय में सौंप दिया गया, जहां उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 366, 376, 302 और 201 के तहत आरोप तय किए गए थे। अपीलार्थी ने किसी भी अपराध को करने से इनकार किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

5. अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए 11 गवाहों से पूछताछ की और प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट सहित बड़ी संख्या में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान में अपीलार्थी की दलील सरल और गलत निहितार्थ से इंकार करना है। हालांकि, किसी भी बचाव पक्ष के गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।

6. घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोप को वापस लाने की मांग की।

ये हैं:

- (i) अपीलकर्ता देवी कांत झा (पीडब्ल्यू-8) के सदन में राजमिस्त्री के रूप में काम कर रहा था

- (ii) अपीलार्थी ने मृतक को पान की दुकान पर भेजा जिससे कि उसे पान मिल सके
- (iii) मृतक के जाने के कुछ मिनट बाद अपीलार्थी बीटल-शॉप की ओर चला गया
- (iv) अपीलार्थी को अंतिम बार मृतक के साथ साइकिल पर जाते हुए देखा गया था और
- (v) अपीलार्थी की संस्वीकृति जिससे खेत से मृत शरीर की बरामदगी हुई।

7. इन सभी परिस्थितियों ने विचारण न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने के लिए प्रेरित किया कि श्रृंखला पूर्ण है जो अपीलार्थी के अपराध की ओर इंगित करती है और तदनुसार उसे ऊपर के रूप में दोषसिद्ध करती है। निचली अदालत की राय में, यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है और तदनुसार इसने मौत की सजा दी। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और दोषसिद्धि की पुष्टि की और ऐसा करते हुए उसने निम्नलिखित मत व्यक्त किया:

".....इसलिए अपीलकर्ता द्वारा दिये गये इकवालिया बयान का भाग जो इस बात का खुलासा करता है कि शव कहाँ पाया जा सकता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत साक्ष्य के रूप में स्पष्ट स्वीकार्य है। चूंकि पीड़ित लड़की पर बलात्कार और हत्या चिकित्सा साक्ष्य द्वारा साबित हो गई है और चूंकि अपीलार्थी द्वारा उसके अपहरण के तुरंत बाद पीड़ित के खिलाफ ऐसे अपराध किए गए थे, अपीलकर्ता के खिलाफ एक धारणा उत्पन्न होती है कि उसने पीड़िता का बलात्कार एवं हत्या की एवं खड़ी फसलों के सुनसान स्थान पर शव को छिपाकर ऐसे अपराध के साक्ष्य को छिपाने की कोशिश की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की धारणा का खंडन किया जा सकता है यदि अपीलकर्ता द्वारा उचित स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कोई स्पष्टीकरण रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया

है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत न तो कोई प्रतिरक्षा गवाह है और न ही गवाहों को कोई उचित सुझाव दिया गया है और न ही अपीलार्थी द्वारा कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। अतः इस उपधारणा का खंडन नहीं किया गया है। अभिलेख पर साक्ष्य और सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के साथ अपीलार्थी द्वारा किए गए प्रकटीकरण, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य है, किसी भी संदेह से परे साबित करते हैं कि अपीलार्थी ने पीड़ित का अपहरण करने के बाद बलात्कार और उसके बाद हत्या का अपराध किया और मृत शरीर को छिपाकर साक्ष्य को नष्ट करने का अपराध भी किया”

8. निर्देश को स्वीकार करते हुए और मृत्युदंड को कायम रखते हुए उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया:

“मैंने पूरे तथ्यों और पूर्वोक्त प्रस्तुतियों पर विचार किया है यह तय करने के लिए कि क्या अपीलार्थी को दी गई मृत्युदंड की पुष्टि की जानी चाहिए या नहीं। इस संबंध में, यह देखा गया है कि अपीलकर्ता लगभग 42-43 वर्ष की उम्र का एक परिपक्व व्यक्ति है। उन्होंने लगभग 7 वर्ष की एक लड़की के बलात्कार और हत्या का जघन्य और बर्बर अपराध किया है, जो पतली और 4 'ऊंचाई की थी। ऐसा बच्चा सामान्य स्थिति में वासना जगाने में असमर्थ था। उसका योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया था क्योंकि वह निर्दोष थी और अपीलकर्ता की योजना को समझ नहीं पाई थी। वह एक पैशाचिक मध्यम आयु के व्यक्ति की असहाय शिकार हो गई, जिस पर बच्चा एक बड़े व्यक्ति के रूप में भरोसा कर सकता था। चिकित्सा साक्ष्य बलात्कार के समय बच्चे के चेहरे, नाखूनों और शरीर पर चोट पहुंचाने के क्रूर तरीके को दर्शाता है, जिसके बाद हत्या की गई। यह सब पूर्व नियोजित था जैसा कि अपहरण करने की रीति एवं अपराध करने के लिए एक निर्जन स्थान का चयन करना एवं शव को

छिपाना था। बच्चियों के खिलाफ इस तरह का अपराध निश्चित रूप से समाज के खिलाफ एक अपराध है। मामले के तथ्यों, पीड़ित की उम्र और अपीलकर्ता की उम्र के साथ लिए गए अपराधों को स्पष्ट रूप से मामले को 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों' की श्रेणी में लाता है जिसमें न्याय के हित में अधिकतम दंड दिए जाने की आवश्यकता होती है।”

9. मृतक की हत्या की गई थी और उसके साथ बलात्कार किया गया था, हमारे सामने पूछताछ नहीं की गई है। हालांकि, अपीलार्थी के विद्वत् वकील ने तर्क दिया है कि अभिलेख पर लाई गई परिस्थितियां अपीलार्थी के अपराध की दिशा में एक और एकमात्र निष्कर्ष नहीं देती हैं और इसलिए अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

10. तथापि, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय का समर्थन करते हैं।

11. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है। हमारी राय में पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोष को सामने लाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि परिस्थितियां अभियुक्त के दोष की ओर एक और एकमात्र निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं। पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है, उन्हें तर्कसंगत और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार साबित की गई परिस्थितियों को निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करना चाहिए। इसे एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इस निष्कर्ष से बच न सके कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई और नहीं। इस पर सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर विचार किया जाना चाहिए, न कि काल्पनिक तरीके से। दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य पूरा होना चाहिए और अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित किया जाना चाहिए। ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध से संगत होना

चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषिता से असंगत होना चाहिए। यह कहने के लिए कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता कि विशेष परिस्थितियां दोष सिद्ध करने के लिए निश्चायक हैं। यह मूल रूप से साक्ष्य के मूल्यांकन का प्रश्न है जिसका प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किया जाना है।

12. उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब हम अभिलेख पर उपलब्ध पारिस्थितिक साक्ष्य पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पीडब्लू-१ राजकुमार झा ने हनुमान चौक पर दुकान रखने वाली ग्राम पंचायत की मुखिया होने का दावा किया और अपने साक्ष्य में कहा है कि अपीलकर्ता देवी कांत झा (पीडब्लू-8) के घर में एक राजमिस्त्री का काम कर रहा था, जो मृतक कल्याणी के दादा थे। उसने दावा किया है कि उसने अपीलार्थी को हनुमान चौक पर आते हुए और अपनी साइकिल पर कल्याणी को बैठाते हुए और उसे इधरटा ग्राम की ओर ले जाते हुए देखा है। उसके बाद कल्याणी कभी नहीं लौटी और न ही अपीलकर्ता शाम तक वापस आया जब तक कि तलाशी शुरू हुई। उसने आगे कहा है कि अपीलार्थी ने गेहूं के खेत में गवाहों का नेतृत्व किया और मृतक कल्याणी का मृत शरीर दिखाया। मृत व्यक्ति के शरीर पर केवल एक पैंटी थी और कोई अन्य कपड़े नहीं थे।

13. पीडब्लू. 2, अमर किशोर झा, की हनुमान चौक में एक दुकान थी और उसने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसने अपीलार्थी को चौक में अपनी साइकिल पर कल्याणी को बैठे हुए देखा था। उसने आगे कहा है कि कल्याणी शाम तक वापस नहीं लौटी और फिर वह पीडब्लू. 1, राज कुमार झा के साथ उसे खोजने गया था। वह अपीलार्थी द्वारा दिए गए बयान का एक गवाह है जिसके कारण कल्याणी के शरीर के विभिन्न स्थानों पर चोट के निशान के साथ उसका मृत शरीर बरामद हुआ। इस चश्मदीद के अनुसार उसके नाखून चबाये गए थे।

14. पीडब्लू. 3, फूल झा, उस पान की दुकान का मालिक है जहां से कल्याणी ने पान खरीदा था। उसके साक्ष्य के अनुसार कल्याणी ने उसकी दुकान से पान खरीदा और जब वह 50 पैसे लौटा रहा था तो उसने उक्त राशि के लिए टॉफी मांगी। उसके साक्ष्य के अनुसार जब कल्याणी दुकान से उतरी, तो अपीलकर्ता एक साइकिल पर आया, उसने उससे पान लिया, उसे साइकिल के वाहक पर बैठाया और उसे दक्षिण दिशा की ओर ले गया। वो अपीलार्थी के संस्वीकृति की गवाह भी है जिससे अपीलार्थी द्वारा इंगित किए गए स्थान पर मृत शरीर की बरामदगी हुई। पीडब्लू. 5, माया देवी एक अन्य गवाह है जिसने अपीलार्थी को मृतक के साथ उसकी साइकिल में देखा था और यहां तक कि अपीलार्थी के साथ हुई बातचीत को देखा था। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने कल्याणी से पूछा कि उसके पिता कहां रहते हैं, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसके पिता बॉम्बे में रहते हैं। पीडब्लू. 6, राधे श्याम झा एक अन्य गवाह है जिसने अपीलार्थी और मृतक को एक साइकिल पर एक साथ देखा था। वह अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान का भी गवाह है, जिससे कल्याणी के मृत शरीर की बरामदगी हुई। पीडब्लू. 8, देबीकांत झा, मृतक के दादा हैं और अपीलार्थी के इकबालिया बयान के आधार पर कल्याणी के मृत शरीर की बरामदगी के गवाह हैं। पीडब्लू. 9, तपेश्वर प्रसाद एक अन्य गवाह है, जो हनुमान चौक में दुकान के मालिक थे और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते थे। उसने कहा है कि कल्याणी द्वारा पान खरीदने के बाद, अपीलार्थी साइकिल पर वहां पहुंचा, उसे साइकिल के वाहक पर बैठाया और दक्षिण दिशा की ओर चला गया। वह अपीलार्थी द्वारा दिया गया कथन के आधार पर कल्याणी के शव की बरामदगी का भी गवाह है। अपीलार्थी द्वारा दिया गया कथन। पीडब्लू. 10, श्रवण कुमार झा, मामले के मुखबिर हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का भी समर्थन किया।

15. उपर्युक्त गवाह के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता मृतक के दादा, पीडब्लू. 8 देबीकांत झा के घर में राजमिस्त्री के रूप में काम कर रहा था और मृतक को उसके द्वारा पान की दुकान पर भेजा गया था। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य सभी उचित संदेह से

परे साबित करते हैं कि अपीलकर्ता मृतक के जाने के कुछ मिनट बाद पान की दुकान की ओर बढ़ा और यह अपीलकर्ता था जिसे अंतिम बार मृतक के साथ साइकिल पर जाते हुए देखा गया था. बहुत सारे सबूत हैं जो किसी भी संदेह की छाया से परे साबित करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए बयान के कारण कल्याणी के शव को खेत से बरामद किया गया. हमारी राय में, इस तरह से साबित हुई परिस्थितियां अपीलार्थी के अपराध की ओर अचूक संकेत करती हैं और श्रृंखला इतनी पूर्ण है कि इस निष्कर्ष से कोई बचने का रास्ता नहीं है कि अपराध अपीलार्थी द्वारा किया गया था और किसी अन्य द्वारा नहीं। तदनुसार, हम अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखते हैं।

16. जैसा कि पहले कहा गया है, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी प्रस्तुत मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में से एक पाया था और तदनुसार मृत्यु दंडादेश दिया था। यह अपीलार्थी के विद्वत वकील द्वारा प्रतिवाद किया गया है कि प्रस्तुत मामला इस प्रकार की श्रेणी के भीतर नहीं आता है और इस प्रकार मृत्यु की अत्यधिक सजा की मांग नहीं की जाती है।

17. यह सामान्य बात है कि मृत्युदंड केवल ऐसे मामले में दिया जा सकता है जो विरलतम मामलों में से विरले मामलों की प्रवर्ग के भीतर आता है किंतु इस जटिल मुद्दे का विनिश्चय करने के लिए कोई कठोर और त्वरित नियम और पैरामीटर नहीं हैं। इस न्यायालय के पास उन मामलों पर विचार करने का अवसर था, जिन्हें दुर्लभ मामलों में से दुर्लभतम कहा जा सकता है और हालांकि इस मुद्दे पर निर्णय देने के लिए कुछ व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इस संबंध में सार्वभौमिक उपयोग का कोई कठोर और तेज फार्मूला निर्धारित नहीं किया गया है। अपराध इतने अलग-अलग और विशिष्ट परिस्थितियों में किए जाते हैं कि व्यापक दिशानिर्देश इस मुद्दे को तय करने के लिए निर्धारित करना असंभव है। फिर भी यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि इस प्रश्न

पर निर्णय लेने में मारे गए व्यक्तियों की संख्या निर्णायक नहीं है। इसके अतिरिक्त, क्रूर और जघन्य अपराध होने के कारण अपराध मृत्युदंड की ओर नहीं बढ़ता। जब अपराध अत्यंत क्रूर, घृणित, शैतानी, विद्रोही या डरपोक तरीके से किया जाता है जिससे कि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक रोष उत्पन्न हो और जब समुदाय की सामूहिक चेतना भयभीत हो जाती है तो व्यक्ति को मृत्युदंड की ओर झुकना पड़ता है। लेकिन यह अंत नहीं है। यदि ये कारक उपस्थित होते हैं तो न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या अभियुक्त समाज के लिए एक खतरा है और उसके शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए खतरा बना रहता है। अदालत को आगे पूछताछ करनी होगी और विश्वास करना होगा कि दोषी ठहराए गए आरोपी को सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है और वह आपराधिक कार्यों को जारी रखेगा। इस प्रकार गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों में मृत्युदंड के अधिरोपण पर विचार करते समय एक तुलनपत्र तैयार किया जाना चाहिए और न्यायसंगत संतुलन बनाया जाना चाहिए। जब तक मृत्युदंड का उपबंध कानून में किया जाता है और जब समुदाय की सामूहिक चेतना भयभीत हो जाती है, तो यह आशा की जाती है कि न्यायिक शक्ति का दमन नहीं किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत राय प्रकट नहीं की जानी चाहिए और मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। ये इस न्यायालय के साथ मृत्युदंड अधिरोपित करने के लिए अधिकथित व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

18. जब हम वर्तमान मामले का परीक्षण इस बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि क्या देखा गया है, तो हमारी राय है कि प्रस्तुत मामला दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। अपीलकर्ता लगभग 43 वर्ष का एक परिपक्व व्यक्ति है। वह विश्वास की स्थिति में थे और उन्होंने योजनाबद्ध और पूर्व नियोजित तरीके से इसका दुरुपयोग किया। उसने लगभग 7 वर्ष की लड़की को पान खरीदने के लिए भेजा और उसके कुछ मिनट बाद अपनी पैशाचिक और विकृत इच्छा को पूरा करने के लिए उस दुकान की ओर बढ़ा जहां उसे भेजा गया था। लड़की लगभग 7 वर्ष की पतली और 4 फीट ऊंची थी और ऐसा बच्चा

सामान्य स्थिति में वासना जगाने में असमर्थ था। अपीलार्थी ने बच्चे का विश्वास जीता था और वह अपीलार्थी की इच्छा को नहीं समझती थी जो इस तथ्य से स्पष्ट होगा कि जब उसे अपीलार्थी द्वारा ले जाया जा रहा था, तब कोई विरोध नहीं किया गया था और निर्दोष बच्चे को अपीलार्थी की लालसा का शिकार बनाया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बच्चे के चेहरे, नाखून और शरीर पर विभिन्न चोटों को दिखाया गया है। ये चोटें उस वीभत्स तरीके को दर्शाती हैं जिसमें उसके साथ बलात्कार किया गया था। अपराध का शिकार एक मासूम बच्चा होता है जिसने हत्या के लिए कोई बहाना भी नहीं बनाया एवं हत्या के लिए उल्लेखित करना। एक छोटे बच्चे के प्रति इस तरह की क्रूरता भयावह है। अपीलार्थी इतना नीचे गिर गया था कि निर्दोष, असहाय और असुरक्षित बच्चे पर अपना दैत्य आत्म छोड़ दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस कृत्य ने समुदाय में अत्यधिक रोष पैदा कर दिया था और समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया था। न्याय करने की शक्ति के साथ प्रदत्त प्राधिकारी से उनकी अपेक्षा है कि वे मृत्युदंड दें जो प्राकृतिक और तार्किक है। हमारा विचार है कि अपीलार्थी समाज के लिए एक खतरा है और ऐसा ही रहेगा और उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रस्तुत मामला दुर्लभ मामलों में से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है और निचली अदालत ने सही तरीके से मौत की सजा दी थी जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने सही तरीके से की थी।

19. परिणाम में, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

.....(हरजीत सिंह बेदी), न्यायमूर्ति

.....(चन्द्रमौली कृष्ण प्रसाद), न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

20 अप्रैल, 2011